

## भारत का कार्बन बाज़ार: एक हरति प्रगति

यह संपादकीय 12/11/2024 को 'द हट्टू' में प्रकाशित "Giving shape to India's carbon credit mechanism" पर आधारित है। यह लेख COP-29 में कार्बन फाइनेंस और क्रेडिट फ्रेमवर्क की महत्त्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करता है, जो भारत के अपने घरेलू कार्बन बाज़ार को विकसित करने के प्रयासों पर केंद्रित है। यह दो प्रमुख चुनौतियों: ग्रीनवाशिंग से बचने के लिये कार्बन क्रेडिट की अखंडता सुनिश्चित करने और विशेष रूप से पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाने पर प्रकाश डालता है।

### प्रलिस के लिये:

[COP-29, राष्ट्रीय सतर पर निर्धारित योगदान, कार्बन मार्केट, पेरिस समझौता, ग्रीनवाशिंग, ग्रीनहाउस गैस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, EU-ETS, प्रदर्शन उपलब्धविद्यापार \(PAT\) योजना, ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022, स्मार्ट सटिज़ मशिन](#)

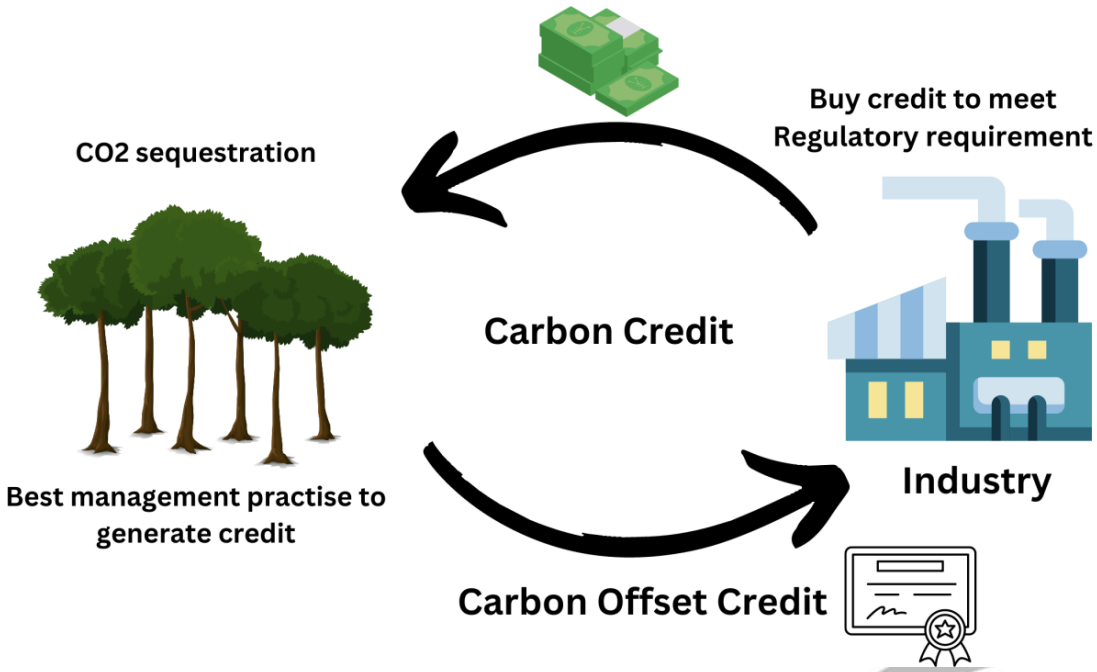
### मेन्स के लिये:

घरेलू कार्बन बाज़ार विकसित करने में भारत के लिये अवसर, भारत में कार्बन बाज़ार के विकास से संबंधित प्रमुख मुद्दे।

बाकू, अज़रबैजान में COP-29 के आयोजन के दौरान कार्बन फाइनेंस और क्रेडिट फ्रेमवर्क विकसित एवं विकासशील देशों के बीच चर्चा के महत्त्वपूर्ण बटु बनकर उभरे हैं। भारत, वर्ष 2023 में अपने राष्ट्रीय सतर पर निर्धारित योगदान को अपडेट करने के बाद, अपने घरेलू कार्बन बाज़ार को विकसित करने के लिये तैयार है। हालाँकि वैश्विक अनुभव दो महत्त्वपूर्ण चुनौतियों को उजागर करते हैं: ग्रीनवाशिंग को रोकने के लिये कार्बन क्रेडिट की अखंडता को बनाए रखना और अंतरराष्ट्रीय मानकों, विशेष रूप से पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के साथ संरेखण सुनिश्चित करना।

## कार्बन क्रेडिट क्या है?

- कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में: कार्बन क्रेडिट व्यापार योग्य प्रमाण-पत्र हैं जो ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन से बचने या वायुमंडल से अधिक नषिकासन के दावे का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  - ये संस्थाओं को इन दावों को खरीदारों को अंतरित करने की अनुमति देते हैं, जो जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिये उन्हें 'नवृत्त' कर सकते हैं।
- प्रमाणन और इकाइयाँ: क्रेडिट सरकारों या स्वतंत्र निकायों द्वारा प्रमाणित होते हैं और आमतौर पर एक मीट्रिक टन CO<sub>2</sub> के परविरजन या नषिकासन को दर्शाते हैं।
  - अनुपालन और स्वैच्छिक रिपोर्टिंग के लिये 'ऑफसेट' के बजाय कार्बन क्रेडिट को प्राथमिकता दी जाती है।
  - GHG प्रभावों की तुलना करने के लिये 100-वर्षीय ग्लोबल वार्मिंग क्षमता (GWP) का प्रयोग करके उत्सर्जन को CO<sub>2</sub>-समतुल्य (CO<sub>2</sub>e) में मानकीकृत किया जाता है।
- वैकल्पिक उपयोग: कार्बन क्रेडिट का उपयोग दावों की भरपाई किये बिना भी किया जाता है, तथा इसका उपयोग केवल जलवायु शमन में किया जाता है।
  - इसके लिये उच्च गुणवत्ता वाले क्रेडिट की आवश्यकता होती है जो कड़े मानदंडों को पूरा करते हों।



## घरेलू कार्बन बाज़ार विकसित करने में भारत के लिये क्या अवसर हैं?

- आर्थिक मूल्य सृजन और बाज़ार का आकार:** भारत कार्बन क्रेडिट का एक महत्वपूर्ण नरियातक है और इसने वर्ष 2010 और 2022 के दौरान स्वैच्छिक कार्बन बाज़ारों में 278 मिलियन क्रेडिट जारी किये हैं, जो वैश्विक आपूर्ति का 17% है।
  - व्यापार के अतिरिक्त, यह बाज़ार कार्बन क्रेडिट सत्यापन एजेंसियों, हरति वित्त संस्थाओं और पर्यावरण परामर्श फर्मों के लिये अवसर उत्पन्न करता है, जिससे संभावित रूप से 200,000 से अधिक नई नौकरियों का सृजन होगा।
  - गुणक प्रभाव भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, साथ ही सतत विकास को भी बढ़ावा दे सकता है।
- अंतरराष्ट्रीय जलवायु नेतृत्व:** विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक तथा नवीकरणीय ऊर्जा अंगीकरण में अग्रणी होने के नाते, भारत वैश्विक जलवायु वित्त संरचना को आयाम देने के लिये अपने कार्बन बाज़ार का लाभ उठा सकता है।
  - अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों में हाल का नेतृत्व जलवायु कार्रवाई का नेतृत्व करने की भारत की क्षमता को दर्शाता है।
  - कार्बन बाज़ार जलवायु वार्ताओं में भारत की स्थिति को मज़बूत बना सकता है, विशेष रूप से विकासशील देशों के गठबंधनों में, साथ ही दक्षिण-दक्षिण सहयोग और प्रौद्योगिकी अंतरण के अवसर भी उत्पन्न कर सकता है।
- औद्योगिक प्रतिसिपद्धात्मकता और नवाचार:** कार्बन मूल्य निर्धारण विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक आधुनिकीकरण और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है।
  - उद्योग दक्षता में सुधार के लिये कार्बन बाज़ार का लाभ उठा सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे EU-ETS ने वर्ष 2005 से औद्योगिक उत्सर्जन को 41% तक कम करने में मदद की है।
  - इससे स्वदेशी स्वच्छ/हरति प्रौद्योगिकियों के विकास के अवसर उत्पन्न होते हैं, विशेषकर सीमेंट और इस्पात जैसे कठिन उद्योगों में।
  - JSW स्टील की कार्बन कटौती पहल जैसी हाल की सफलता की कहानियाँ भारतीय उद्योग के लिये कम कार्बन उत्सर्जन उपायों में अग्रणी बनने की क्षमता दर्शाती हैं।
- डिजिटल अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी एकीकरण:** भारत का मज़बूत डिजिटल अवसंरचना पारदर्शी, कुशल कार्बन बाज़ार बनाने के लिये वशिष्ट अवसर प्रस्तुत करता है।
  - UPI और COWIN जैसी डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं की सफलता परिष्कृत कार्बन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिये एक टेम्पलेट प्रदान करती है।
  - ब्लॉकचेन, IoT और AI का एकीकरण कार्बन क्रेडिट सत्यापन एवं व्यापार में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, लागत कम कर सकता है तथा पारदर्शिता बढ़ा सकता है।
  - इससे भारत जलवायु कार्रवाई के लिये डिजिटल समाधान में अग्रणी बन सकता है।
- हरति निवेश उत्प्रेरक:** एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया कार्बन बाज़ार महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय हरति वित्त को आकर्षित कर सकता है।
  - उभरते बाज़ारों (चीन को छोड़कर) में वदेशी वित्तपोषण में ESG निवेश का हिस्सा अब लगभग 18% है।
  - भारत का कार्बन बाज़ार इस पूंजी को स्थायी परियोजनाओं, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और वन संरक्षण में निवेश के लिये एक संरचित मार्ग प्रदान कर सकता है। बाज़ार तंत्र भारत के हरति बॉण्ड और स्थायी वित्त पहलों का भी समर्थन कर सकता है।
- ग्रामीण विकास और कृषि परिवर्तन:** कार्बन बाज़ार कृषि और वानिकी कार्बन क्रेडिट के माध्यम से ग्रामीण भारत के लिये वशिष्ट अवसर प्रस्तुत करते हैं।
  - महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हाल ही में संचालित पायलट परियोजनाओं से पता चलता है कि किसान कार्बन कृषि के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं।
  - वे नरि्वनीकरण (वनों की कटाई) और कार्बन राजस्व से प्रतविर्ष 65,000 रुपए प्रति एकड़ तक अर्जित कर रहे हैं, जबकि धान की कृषि से उन्हें मात्र 10,000 रुपए प्रति एकड़ की आय हो रही है।

- संरचित बाज़ार **संधारणीय कृषि, कृषिवानिकी** और **ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं** को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से किसानों को लाभ होगा तथा साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं जलवायु अनुकूलन को भी बढ़ावा मल्लिगा ।
- **क्षेत्र परिवर्तन के अवसर:** वभिन्न क्षेत्र वशिष्ट अवसर प्रस्तुत करते हैं: ऊर्जा क्षेत्र **नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण** में तेज़ी ला सकता है, वनरिमाण क्षेत्र **दक्षता में सुधार के लिये धन** जुटा सकता है, रयिल एस्टेट क्षेत्र हरति भवन को अपनाने में तेज़ी ला सकता है और परविहन क्षेत्र वदियुत गतशीलता में तेज़ी ला सकता है ।
  - **13 ऊर्जा-गहन क्षेत्रों को शामिल करने वाली परफॉर्मंस अचीव ट्रेड (PAT) योजना** की हाल की सफलता, बाज़ार तंत्र के लिये उद्योग की तत्परता को दर्शाती है ।
  - यह क्षेत्रीय दृष्टिकोण **वशिष्ट कार्बन करेडिट श्रेणियाँ** और व्यापार तंत्र बना सकता है ।
- **ज्ञान अर्थव्यवस्था विकास:** कार्बन बाज़ार का नरिमाण **कार्बन लेखांकन, सत्यापन, व्यापार और जलवायु वतित में वशिषज्जता वकिसति करने के अवसर** उत्पन्न करता है ।
  - इससे **भारत वैश्विक स्तर पर उभरते कार्बन बाजारों के लिये ज्ञान केंद्र** के रूप में स्थापति हो सकता है ।
  - जलवायु वशिषवदियालय नेटवर्क (100 से अधिक वशिषवदियालयों को जोड़ने वाला) जैसी हालिया पहल वशिष कौशल और अनुसंधान क्षमता नरिमाण की संभावनाएँ दर्शाती हैं ।
  - बाज़ार पर्यावरण शक्ति और व्यावसायिक विकास में नवाचार को बढ़ावा दे सकता है ।
- **शहरी स्थरिता एकीकरण:** कार्बन बाज़ार अपशष्टि प्रबंधन, शहरी वानिकी और स्वच्छ परविहन परियोजनाओं के माध्यम से **सतत शहरी विकास** को गता दे सकता है ।
  - **इंदौर** जैसे शहर, जो **अपशष्टि कार्बन करेडिट से राजस्व** उत्पन्न करते हैं, इसकी सम्भावनाओं को दर्शाते हैं ।
  - बाज़ार तंत्र **भारत के स्मार्ट सटिज मशिन को समर्थन** दे सकता है, कम कार्बन अवसंरचना को प्रोत्साहित कर सकता है तथा शहरी स्थानीय नकियाँ के लिये जलवायु पहलों को वतितपोषति करने हेतु नए राजस्व स्रोत सृजति कर सकता है ।

## भारत में कार्बन बाज़ार के विकास से संबंधति प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **बाज़ार डज़िाइन एवं मूल्य नरिधारण जटलिता:** भारत को एक कुशल बाज़ार संरचना तैयार करने में महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो **पर्यावरणीय लक्ष्यों को आर्थिक वास्तवकिताओं के साथ संतुलति कर सके** ।
  - **उचति सीमा** नरिधारति करना, भत्ते आवंटति करना तथा मूल्य अस्थरिता को नयंत्रति करते हुए बाज़ार में चल-नधि सुनश्चिति करना, जटलि नीतगित नरिणयों की आवश्यकता रखता है ।
  - **भारत के औद्योगिक परदृश्य** की वधिधिता, प्रोद्योगिकीय क्षमताओं और उत्सर्जन तीव्रता में भन्निता के कारण एक समान मूल्य नरिधारण तंत्र वशिष रूप से चुनौतीपूर्ण है ।
  - बाज़ार की प्रभावशीलता को बनाए रखते हुए **रणनीतिक क्षेत्रों की सुरक्षा की आवश्यकता** के कारण यह और भी जटलि हो जाता है ।
- **मापन, रपिर्टगि और सत्यापन अवसंरचना: उत्सर्जन डेटा संग्रहण और सत्यापन प्रणालियों में वर्तमान अंतराल** महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं ।
  - **भारत के वधिधि औद्योगिक आधार** के कारण यह चुनौती और भी बढ़ जाती है, क्योंकि **कई छोटे और मध्यम उद्यमों में** सटीक उत्सर्जन नगिरानी के लिये तकनीकी क्षमता का अभाव है । वभिन्न क्षेत्रों में वशिषसनीय आधारभूत उत्सर्जन डेटा स्थापति करना एक बुनयिादी चुनौती बनी हुई है ।
- **नयामक ढाँचा और संस्थागत क्षमता: ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधनियिम, 2022** के बावजूद, महत्त्वपूर्ण नयामक अंतराल बने हुए हैं ।
  - **गरीन करेडिट प्रोगराम** के कार्यान्वयन में हाल में हुए वलिंभ से संस्थागत क्षमता संबंधी बाधाओं पर प्रकाश पड़ता है ।
  - **वभिन्न एजेंसियों (ऊर्जा दक्षता बयुरो, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, CERC)** के बीच समन्वय की आवश्यकता परचिलन जटलिताएँ उत्पन्न करती हैं ।
  - जटलि कार्बन बाज़ार परचिलनों के प्रबंधन के लिये वर्तमान नयामक ढाँचे में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता हो सकती है ।
- **उद्योग की तत्परता और अनुपालन लागत:** कई भारतीय उद्योग, वशिष रूप से MSME, जो **प्रतविरष लगभग 110 मिलियन टन समतुल्य CO2 उत्पन्न करते हैं**, उन्हें बाज़ार में भागीदारी में महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ।
  - **नगिरानी उपकरण, सत्यापन प्रकरया और व्यापारिक बुनयिादी अवसंरचना** सहति अनुपालन की लागत सीमांत भागीदारों के लिये नषिधात्मक हो सकती है ।
  - **कार्बन लेखांकन और व्यापार रणनीतियों** में तकनीकी क्षमता अंतराल कुछ क्षेत्रों तथा क्षेत्रों के लिये नुकसानदेह हो सकता है, जिससे संभावति रूप से बाज़ार में वकित्तियाँ उत्पन्न हो सकती हैं ।
- **अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार एकीकरण मुद्दे:** राष्ट्रीय हतियों की रक्षा करते हुए घरेलू कार्बन बाजारों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना जटलि चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है ।
  - **COP29 में अनुच्छेद 6** की वारता, संबंधति समायोजन और ऋण गुणवत्ता के बारे में चल रही बहस को उजागर करती है ।
  - भारत को अपनी कार्बन परसिपत्तियों पर संप्रभुता बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार अनुकूलता सुनश्चिति करने के बीच संतुलन बनाना होगा ।
  - **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रतसिपर्द्धात्मकता** संबंधी चतियाँ के माध्यम से कार्बन लीकेज के जोखमि को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक नीत-नरिमाण की आवश्यकता है ।
- **दोहरी गणना एवं अतरिकितता संबंधी चतियाँ:** करेडिट इंटगिरटि सुनश्चिति करना और दोहरी गणना को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है ।
  - **स्वैच्छकिय योजनाओं के तहत वानिकी ऋणों** की हाल की आलोचना, जहाँ **30%** तक को अतरिकितता के प्रश्नों का सामना करना पड़ा, सत्यापन चुनौतियों को उजागर करती है ।
  - वभिन्न योजनाओं (**प्रदरशन उपलब्धियापार (PAT) योजना**, **नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र**, **प्रस्तावति कार्बन बाज़ार**) के मध्य ओवरलैप से बहु गणना का जोखमि पैदा होता है ।
  - वभिन्न कार्यक्रमों में **कार्बन करेडिट के लिये स्पष्ट स्वामति अधिकार और ट्रेकिंग तंत्र** स्थापति करने के लिये परषिकृत

प्रणालियों एवं प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है।

- **क्षेत्रीय एवं क्षेत्रवार असमानताएँ:** राज्यों में औद्योगिक विकास और तकनीकी क्षमता में वृहत भिन्नताएँ समानता संबंधी चर्चाएँ उत्पन्न करती हैं।
  - उच्च औद्योगिक संकेंद्रण वाले राज्य (गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान) बाजार गतिशीलता पर हावी हो सकते हैं।
  - इस संभावना पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए कि बाजार लाभ वकिसति क्षेत्रों में केंद्रित हो जाएगा, जबकि कम वकिसति क्षेत्रों पर असंगत लागतें थोपी जाएंगी।
- **प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना अंतराल:** वर्तमान प्रौद्योगिकी अवसंरचना परषिकृत कार्बन बाजार परचालनों के लिये अपर्याप्त हो सकती है।
  - अंतरराष्ट्रीय कार्बन रजिस्ट्री में साइबर सुरक्षा उल्लंघन प्रौद्योगिकी जोखिमों को उजागर करते हैं।
    - जनवरी 2011 में, हैकरों ने चेक कार्बन रजिस्ट्री के मुख्यालय पर बम की धमकी जारी करके, वहाँ से लगभग 1.2 मिलियन क्रेडिट चुरा लिये।
  - सुरक्षा, पारदर्शी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, विश्वसनीय नगरानी प्रणाली और सत्यापन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिये बहुत बड़े निवेश की आवश्यकता होती है।
  - क्षेत्रों और उद्योगों के बीच डिजिटल डिविड परचालन संबंधी चुनौतियाँ और बाजार पहुँच संबंधी समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है।
- **बाजार में हेरफेर और सट्टेबाजी का जोखिम:** अन्य बाजारों के अनुभव से पता चलता है कि मूल्य में हेरफेर और अत्यधिक सट्टेबाजी की संभावना अधिक है।
  - एक जाँच में पाया गया कि वेरा द्वारा वर्षावन कार्बन ऑफसेट का 90% से अधिक हिससा, जिसका डिज़िनी और शेल जैसी कंपनियों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, 'फ्रैटम क्रेडिट' हो सकता है, जिसका उत्सर्जन पर बहुत कम वास्तविक प्रभाव पड़ता है।
  - इसके अलावा, गरीनवाशिग- जहाँ कंपनियाँ संदिग्ध ऑफसेट का प्रयोग करके कार्बन तटस्थता का दावा करती हैं- बाजार की विश्वसनीयता और उपभोक्ता विश्वास के लिये जोखिम उत्पन्न करती है, जिससे कार्बन बाजारों की अखंडता एवं अधिक जटिल हो जाती है।

## कार्बन बाजार के विकास में तेज़ी लाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति:** उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्रों (वैद्युत ऊर्जा, सीमेंट, इस्पात) से शुरू करते हुए एक स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, जहाँ PAT योजना के तहत नगरानी क्षमताएँ पहले से मौजूद हैं।
  - छोटे उद्योगों में क्षमता निर्माण करते हुए धीरे-धीरे मध्यम-उत्सर्जन क्षेत्रों में वसितार करना चाहिये।
  - यह उपागम, चीन की सफल उत्सर्जन व्यापार प्रणाली की भांति, संस्थागत क्षमता का निर्माण करते हुए बाजार को परिपक्वता प्रदान करता है।
- **एकीकृत डिजिटल अवसंरचना:** पारदर्शी ट्रेडिंग और ट्रेडिंग के लिये ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को एकीकृत करते हुए एक एकीकृत कार्बन रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म वकिसति करने की आवश्यकता है।
  - मानकीकृत डिजिटल रपिपोर्टिंग प्रारूपों को अनिवार्य तथा विभिन्न प्रणालियों में नरिबाध डेटा एकीकरण के लिये API बनाया जाना चाहिये।
  - IoT सेंसर और स्वचालित डेटा सत्यापन का उपयोग करके रथिल टाइम मॉनिटरिंग और सत्यापन प्रणाली लागू किया जाना चाहिये। यह डिजिटल फ्रेमवर्क वनिमिय की लागत को कम करेगा और बाजार की पारदर्शिता को बढ़ाएगा।
- **क्षमता निर्माण पारस्थितिकी तंत्र:** उद्योग पेशेवरों, लेखा परीक्षकों और नयामकों को लक्षित करते हुए एक समर्पित कार्बन बाजार कौशल विकास कार्यक्रम स्थापित किया जाना चाहिये।
  - कार्बन बाजार पेशेवरों और सत्यापन एजेंसियों के लिये मानकीकृत प्रमाणन कार्यक्रम बनाए जाने चाहिये। उत्सर्जन गणना और रपिपोर्टिंग के लिये उद्योग-वशिषिट मार्गदर्शन तथा उपकरण बनाए जाने चाहिये।
- **गतिशील मूल्य प्रबंधन प्रणाली:** अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिये न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों के साथ प्राइस कॉलर तंत्र को लागू करने तथा सारथक कार्बन मूल्य नरिधारण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
  - आपूर्ति-मांग संतुलन को प्रबंधित करने के लिये EU-ETS के समान एक बाजार स्थिरता रज़िर्व बनाया जाना चाहिये।
  - तकनीकी क्षमताओं और अंतरराष्ट्रीय प्रतस्पर्द्धात्मकता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र-वशिषिट भत्ता आवंटन पद्धति वकिसति करना चाहिये।
- **क्षेत्रीय एकीकरण फ्रेमवर्क:** भारत के NDC के अनुरूप क्षेत्र-वशिषिट उत्सर्जन तीव्रता मानक और कटौती के मार्ग तैयार करने की आवश्यकता है।
  - दोहरी गणना को रोकने के लिये मौजूदा योजनाओं (PAT, REC) को कार्बन बाजार से जोड़ने के लिये तंत्र वकिसति करना चाहिये।
  - कैप-एंड-ट्रेड के अंतर्गत शामिल न होने वाले क्षेत्रों से परियोजना-आधारित क्रेडिट के लिये स्पष्ट प्रोटोकॉल स्थापित करना चाहिये।
  - वैकल्पिक अनुपालन तंत्रों सहित हार्ड-टू-ऐबेट क्षेत्रों के लिये वशिषिट प्रावधान तैयार किया जाना चाहिये। सामूहिक भागीदारी और ज्ञान साझा करने के लिये उद्योग समूह बनाए जाने चाहिये।
- **अंतरराष्ट्रीय संरक्षण:** प्रारंभ से ही अनुच्छेद 6 की ज़रूरतों के अनुरूप कार्बन बाजार अवसंरचना का विकास करने की आवश्यकता है।
  - अंतरराष्ट्रीय ऋण अंतरण और तदनु रूप समायोजन के लिये स्पष्ट फ्रेमवर्क तैयार किया जाना चाहिये।
  - बाजार को जोड़ने और क्षमता निर्माण के लिये द्विपक्षीय साझेदारियाँ स्थापित की जानी चाहिये।
- **क्षेत्रीय विकास फ्रेमवर्क:** स्थानीय समर्थन और नगरानी के लिये राज्य स्तरीय कार्बन बाजार प्रकोष्ठों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता है।
  - स्थानीय औद्योगिक प्रोफाइल पर विचार करते हुए क्षेत्रीय कार्बन बाजार विकास योजनाएँ वकिसति की जानी चाहिये।
  - भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये राज्यों के साथ राजस्व साझा करने हेतु तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये।

## नषिकर्ष:

भारत के कार्बन बाज़ार में सतत विकास के लिये अपार संभावनाएँ हैं। बाज़ार डिज़ाइन, डेटा इंटीग्रिटी और वनियामक फ्रेमवर्क जैसी चुनौतियों का समाधान करके, भारत एक मज़बूत एवं कुशल बाज़ार बना सकता है। इससे उत्सर्जन में कमी आएगी, हरित नविश आकर्षित होगा और भारत जलवायु कार्रवाई में वैश्विक अभिकर्ता के रूप में स्थापित होगा।

????? ?????:

प्रश्न. जलवायु शमन के लिये एक उपकरण के रूप में कार्बन ट्रेडिंग की भूमिका पर चर्चा कीजिये। विकासशील देशों पर पड़ने वाले प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसकी क्षमता का विश्लेषण कीजिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न 1. नमिनलखिति में से कौन-सा कथन 'कार्बन के सामाजिक मूल्य' पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? (2020)

आर्थिक मूल्य के रूप में यह नमिनलखिति में से कसिका माप है?

- (a) प्रदत्त वर्ष में एक टन CO के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति
- (b) कसिी देश की जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता, जनिहें जलाकर देश अपने नागरकों को वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करता है
- (c) कसिी जलवायु शरणार्थी (Climate refugee) द्वारा कसिी नए स्थान के प्रति अनुकूलति होने हेतु कयि गए प्रयास
- (d) पृथ्वी ग्रह पर कसिी व्यक्तिविशेष द्वारा अंशदत कार्बन पदचहिन

उत्तर: (a)

प्रश्न 2. "कार्बन क्रेडिट" के संबंध में, नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा सही नहीं है? (2011)

- (a) कार्बन क्रेडिट प्रणाली को क्योटो प्रोटोकॉल के साथ अनुमोदति कयि गया
- (b) कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदान कयि जाता है जनिहोंने ग्रीनहाउस गैसों को अपने उत्सर्जन कोटा से नीचे ला दयिा है
- (c) कार्बन क्रेडिट प्रणाली का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की वृद्धि को सीमति करना है
- (d) कार्बन क्रेडिट का कारोबार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समय-समय पर तय की गई कीमत पर कयिा जाता है।

उत्तर: (d)

प्रश्न 3. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2023)

कथन-I: ऐसी संभावना है कि कार्बन बाज़ार, जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए।

कथन-II: कार्बन बाज़ार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरति कर देते हैं।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा एक सही है?

- (a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है।
- (b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।
- (c) कथन-I सही है कति कथन-II गलत है।
- (d) कथन-I गलत है कति कथन-II सही है।

उत्तर: (b)

??????:

Q. क्या यू.एन.एफ.सी.सी.सी. के अधीन स्थापति कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास यांत्रिकित्वों का अनुसरण जारी रखा जाना चाहयि, यद्यपि कार्बन क्रेडिट के मूल्य में भारी गरिावट आई है? आर्थिक संवृद्धि के लयि भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की दृष्टि से चर्चा कीजयि। (2014)

